शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

मप्र बोर्ड : 9वीं, 11वीं का रिजल्ट 15 मई को

भोपाल। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम 15 मई तक घोषित कर देंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पहले 30 अप्रैल तक रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संक्रमण को देख इसे बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया है। सभी स्कूलों को 20 मई तक विमर्श पोर्टल पर रिजल्ट एंट्री करने को कहा गया है।

मप्र बोर्ड के सरकारी स्कूलों की नौंवीं व 11वीं का परीक्षा परिणाम 15 मई को

भोपाल (नप्र)। मप्र बोर्ड से संबद्ध सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 15 मई को घोषित किया जाएगा। इस संबंध में लोकशिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 30 अप्रैल को घोषित किया जाने वाला परीक्षा परिणाम अब 15 मई तक घोषित किया जाएगा। सभी संभागीय संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधकिारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि परीक्षा परिणाम संबंधी जानकारी विमर्श पोर्टल पर 15 मई तक दर्ज करवाएं। बता दें, कि मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले आदेश जारी कर नौंवीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त कर रिवीजन टेस्ट और छमाही परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करते हुए रिजल्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं व प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी

नई दिल्ली(ब्यूरो)।देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की आगामी सभी प्रस्तावित परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। यूजीसी जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपने ज्यादा से ज्यादा कोर्सों को आनलाइन या फिर दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों से संचालित करने का फैसला किया है।

NSUI ने की मांग

ओपन बुक से कराई जाएं 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं

भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर एनएसयूआई के भव्य सक्सेना ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखकर 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से करवाने की मांग की है। भव्य सक्सेना ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ऑफलाइन एग्जाम कराना विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा जिससे विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान है।

स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को लिखा पत्र

शिक्षाविदों का कहना है कि 10वीं और 12वीं परीक्षाएं विद्यार्थियों की आधारशिला होती हैं। उक्त दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट से विद्यार्थियों का भविष्य तय होता है। क्योंकि 10वीं के रिजल्ट पर विद्याथीट आर्ट, कामर्स और साइंस में प्रवेश लेता है। वहीं 12वीं पास होने के बाद विद्यार्थी नौकरी और उद्योग की तरफ बढ़ने डिग्री करने प्रवेश लेने की व्यवस्था जमाता है। ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं होने पर सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हो जाएंगे। रिजल्ट मिलने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों की योग्य और अयोग्य में अंतर नहीं कर पाएंगे।

नए शैक्षिणक सत्र से होगा लागू फैसला

सीबीएसई ने कक्षा 9,10,11 व 12वीं में परीक्षा का पैटर्न बदला

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं चारों कक्षाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। सीबीएसई का नया एग्जाम पैटर्न शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा। क एकेडेमिक सेशन 2021-22 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने नया असेसमेंट और ईवैल्यूएशन पैटर्न तैयार किया है। बोर्ड के ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट विभाग के निदेशक ▶▶ शेष पेज 6 पर

कक्षा 9-10 के लिए ऐसा पैटर्न

कक्षा 9वींऔर 10वीं की परीक्षा में कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 कर दिये गये हैं। इसमें मल्टीपल च्वाइस, केस आधारित और कोर्स आधारित इंटीग्रेडेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं, प्रश्नपत्र के 20% सवाल ▶▶ शेष पेज 6 पर

कक्षा 11-12 के लिए ये बदलाव

क्लास 11वीं और 12वीं की बात करें, तो पिछली बार की तरह कंपीटेंसी बेस्ड सवाल 20% होंगे। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों की संख्या 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। वहीं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप सवाल 70% से घटाकर 60% कर दिए गए हैं।

दिसंबर में 25 फीसदी राशि देने के आदेश हुए थे जारी

शिक्षकों को तीसरी किस्त के भुगतान का इंतजार

भोपाल। राजधानी के ज्यादातर शिक्षकों को सातवें वेतन की तीसरी किस्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मप्र शिक्षक कांग्रेस ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिसंबर में तीसरी किस्त की 25 फीसदी राशि देने के आदेश जारी हुए थे। पिछले मार्च में 75 फीसदी राशि का भुगतान करने के आदेश हुए इसके बावजूद अभी तक शिक्षकों को तीसरी किस्त नहीं मिल सकी। फंदा ब्लॉक के प्रत्येक शिक्षक को लगभग 70 से 80 हजार रुपए का भुगतान किया जाना था, जो अब तक नहीं किया गया। डीईओ नितिन सक्सेना का कहना है कि कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हैं, जो दफ्तर नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर शिक्षकों को भुगतान किया जा चुका है बाकी के बिल बन चुके हैं।

आदेश जारी होने के बाद भी दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को नहीं मिल रही अनुग्रह राशि

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 366 शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन दिवंगत के आश्रित परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए संबंधित परिवार या संस्था प्रमुख की ओर से संकुल केंद्र में पदस्थ वेतन आहरण अधिकारी को सूचना भेजी जाती है। बावजूद अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कार्यालय बंद रहने के चलते दिवंगतों के आश्रितों को तात्कालिक सहायता के रूप में मिलने वाली 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि तक नसीब नहीं हो रही है। लोक शिक्षण संचालनालय विभाग ने मार्च में नौ मार्च को एक आदेश जारी कर यह दिशा-निर्देश जारी किए थे कि अनुग्रह राशि का भुगतान आश्रित परिजनों को उसी दिन तत्काल दी जाए, लेकिन इसके बाद भी भुगतान में देरी हो रही है। पूरे प्रदेश में 1809 शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं और 366 की मौत हो चुकी है।

संविदा कर्मचारियों को मिले इलाज के लिए ढाई लाख

भोपाल। सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि संविदा कर्मचारियों को भी कोविड-19 के इलाज के लिए ढाई लाख रुपए दिए जाएं। संघ के अध्यक्ष ने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में करीब ढाई लाख संविदा कर्मचारी हैं, जो नियमित कर्मचारियों के समान ही कार्य करते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ की मांग

आनलाइन कक्षाओं पर रोक, फीस पर फैसला नहीं

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आनलाइन कक्षाओं को कोरोना संक्रमण की वजह से बंद करने का फरमान तो जारी हो गया, लेकिन फीस के मुद्दे पर शासन की चुप्पी बनी हुई है। इधर, निजी स्कूल किसी भी तरह विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। आनलाइन कक्षाओं के दौरान ही विद्यार्थियों को फीस जमा करवाने की हिदायत दी जा रही है। वहीं लाकडाउन की वजह से अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे फीस जमा की जाए। स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में पूरी फीस मांग रहे हैं।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने सिर्फ निजी स्कूलों से ट्यूशन फीस लेने के निर्देश दिए थे। वो भी बिना किसी दबाव के लिए जाना था। इसके लिए स्कूलों को किस्त में राशि ली जानी थी। यदि किसी अभिभावक द्वारा फीस नहीं जमा की गई है उसके बावजूद विद्यार्थी को कक्षा और परीक्षा ना ही नतीजे रोकने की अनुमति स्कूल प्रबंधन को थी। अब नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। आनलाइन कक्षाएं भी लग रही हैं। ऐसे में स्कूलों ने पहले ही अभिभावकों को पूरी फीस जमा करने के लिए संदेश जारी करना शुरू कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि फीस पूरी भरें यदि किसी तरह की बाद में सरकारी आदेश जारी होते हैं तो अतिरिक्त भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जाएगा। इधर स्कूल खुलने से पहले दोबारा लाकडाउन लग चुका है। संक्रमण की भयावहता को देखकर अभिभावक फिलहाल अगले कई माह तक स्कूलों में विद्यार्थियों को भेजने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बंद कक्षाओं के लिए फीस वसूलना अभिभावकों की दृष्टि से जायज नहीं माना जा रहा है।

एक मई से आनलाइन कक्षाओं पर पाबंदी

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी आनलाइन कक्षाओं पर एक मई से रोक लगा दी है। ये पाबंदी एक माह तक लागू रहेगी। अब कक्षा 1 से लेकर 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी 31 मई तक आनलाइन क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण लगातार फैलने के कारण विद्यार्थियों में भय व तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। इस कारण 10वीं और 12वीं बोर्ड को छोड़कर अन्य कक्षाओं की आनलाइन कक्षाएं एक मई से 31 मई 2021 तक के लिए निरस्त की जा रही है। ये आदेश मप्र बोर्ड के अलावा केंद्रीय बोर्ड और आइसीएससी बोर्ड के स्कूलों पर भी लागू होगा।

कोरोना से शिक्षकों की मौत का चार सौ तक पहुंचा आंकड़ा, कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग

शहर प्रतिनिधि, भोपाल । राजधानी समेत प्रदेश में शिक्षकों की मौत का आंकड़ा चार तक पहुंच गया है। शिक्षक समेत कई कर्मचारी संगठनों ने शिक्षक संवर्ग को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है। राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस त्रासदी में प्रदेश का कर्मचारी जगत पूर्ण लगन एवं निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहा है। करोना फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कई विभागों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रासंगिक लाभ दिए जा रहे हैं। यही प्रदेश में एक ऐसा संवर्ग है जो ग्राम स्तर से लेकर शहरी स्तर तक कोरोना के महामारी के निदान में अपनी सेवाएं देता आ रहा है। शिक्षक संवर्ग ऐसा संवर्ग है जिसकी ड्यूटी राज्य के प्रशासनिक अधिकारी जहां उचित होता है वही लगा देते है। जैसा की उज्जैन जिले में कलेक्टर ने आदेश किया है कि जिले के प्रत्येक नगर और गांव में सभी शिक्षक सर्दी बुखार और खांसी के मरीजों का सर्वे करेंगे। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता यहां तक कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी स्वच्छी तक को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है और फ्रंटलाइन वर्कर माना गया है तो शिक्षक क्यों नहीं। जितेंद्र सिंह का कहना है कि शिक्षकों की कोरोना से मौत हो रही है। शिक्षकों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिए जाए। वहीं, मप्र शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुभाष सक्सेना का कहना है कि कोरोना ड्यूटी में कार्यरत शिक्षकों को कोरोना योद्धा माना गया है, लेकिन पूरे संवर्ग को कोरोना योद्धा घोषित किया जाना चाहिए। वहीं, मप्र विद्युत कर्मचारी संघ इंटक के महामंत्री बीडी गौतम ने बिजली विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है।

आउट कर्मचारियों का बीमा कराने की मांग: सेमी गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन ने निगम मंडलों में आउट सोर्स एवं विभिन्न कंपनियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने की मांग की गई है। संघ के संरक्षक अनिल खाजपेयी का कहना है कि हाल ही में पेयर हाउस कारपोरेशन के फील्ड कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का आदेश दिया है। बीमा राशि प्रीमियम का भुगतान संस्थान द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार निगम मंडलों एवं शासन कि कई संस्थाओं में आउट सोर्स विभिन्न कंपनियों के माध्यम से जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनका बीमा कराया जाए। ताकि कोरोना काल जैसी प्राकृतिक विपदा के समय किसी प्रकार की अनहोनी घटना के घटित होने पर आर्थिक राशि प्राप्त हो और परिवार को राहत प्रदान हो सके।

अफसरों के आदेश के बाद भी छात्रावास वार्डनों की जांच रिपोर्ट नहीं दे रहे डीपीसी

श्योपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला मुख्यालय पर डीपीसी कार्यालय द्वारा संचालित छात्रावासों में लंबे समय से नियम विरुद्ध तरीके से वार्डन बनकर रह रहीं शिक्षिकाओं की शिकायत के मामले में बार-बार आदेश दिए जाने के बाद भी जिले के डीपीसी सक्षम अधिकारियों के समक्ष जांच प्रतिवेदन नहीं सौंप रहे हैं।

इससे जिले के आला अधिकारी उक्त प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर ने भी डीपीसी को स्मरण पत्र भेजकर जांच प्रतिवेदन सौंपे जाने के लिए लिखा जा चुका है। इसके बाद भी उनके द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा जानकारी दी गई है कि, जिला मुख्यालय के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में पदस्थ वार्डन पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय से छात्रावास में नियम विरुद्ध तरीके से वार्डन बनी हुई है। नियमानुसार वार्डन का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत पर डीपीसी द्वारा बनाई गई पूर्व की जांच टीम भी उनके खिलाफ रिपोर्ट सौंपकर उन्हें छात्रावास के वार्डन पद से हटाए जाने की अनुशंसा कर चुकी है। लेकिन, अधिकारियों ने जांच टीम की रिपोर्ट को मानने की बजाए, फिर से जांच दल गठित करके उक्त प्रकरण में वार्डन को बचाए जाने की कोशिश की जा रही है।

24 घंटे के दौरान ही अलग-अलग स्कूलों में पदस्थ पांच अध्यापकों ने तोड़ा दम

राजगढ़ जिले में कोरोना से 9 दिन में 26 शिक्षकों की मौत

इन 23 शिक्षकों के अलावा 01 लिपिक और 01 बीएसी भी कोविड-19 से मृत मप्र शासकीय अध्यापक संगठन ने की शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग

सुनील गोले ▶▶राजगढ़

कोरोना की दूसरी लहर में वायरस का नया स्टेन मानव जीवन के लिए घातक बना हुआ है। इस दूसरी लहर में अब तक एक सैकड़ा से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं। बड़ी और चौंकाने वाली बात यह भी है कि बीते नौ दिनों में राजगढ़ जिले के 26 शिक्षकों की मौत इस वैष्विक महामारी से हुई है।

इन 26 शिक्षकों के अलावा शिक्षा विभाग के एक लिपिक सहित राजगढ़ बीआरसी कार्यालय में पदस्थ बीएसी संजीव सक्सेना भी इस महामारी के चलते अब हमारे बीच नहीं हैं। शिक्षक संघों द्वारा मांग की जा रही है कि शासन द्वारा अधिकतर विभागों के कर्मचारियों को दी जा रही मुख्यमंत्री कोविड योद्धा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। संघ पदाधिकारियों का तर्क है कि शिक्षकों एवं अध्यापकों की ड्यूटी भी कोरोना के संक्रमण काल में विभिन्न जगह लगाई जा रही है।

जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय(डीईओ) द्वारा भी एक लिंक प्रतिदिन जिले के सभी स्कूलों के प्राचार्यों को दी जा रही है कि कितने शिक्षक/कर्मचारी संक्रमित हुए हैं एवं कितनों का निधन हुआ है। उक्त लिंक के अनुसार ही जिले से बीते नौ दिन में 23 शिक्षक कोरोना से काल के गाल में समाए हैं।

24 घंटे में कोरोना से 5 शिक्षकों ने तोड़ा दम

बीते 24 घंटों में ही जिले के 5 अलग-अलग स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है। इन मृतक शिक्षकजनों में राजगढ़ हायर सेकन्ड्री स्कूल में पदस्थ शिक्षिका ऊषा विजयवर्गीय, माध्यमिक शिक्षक राजू सौंधिया तहसील राजगढ़, सुरेष एक्का प्रावि तुर्कीपुरा नरसिंहगढ़, रामप्रसाद मालवीय अध्यापक प्रावि खेड़ी गौतमपुरा माचलपुर एवं बिरुलाल मालवीय, हाईस्कूल लखेसरा पचोर शामिल हैं।

शासन से रखी कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग

शिक्षा विभाग के शिक्षकों सहित संघटना के पदाधिकारियों धर्मेंद्र शर्मा, रामबाबू शर्मा, मांगीलाल चौहान, कमल सिंह चौहान, केपी शाक्यवार, देवीलाल मालवीय, कुमेर सिंह लोधी, कालूसिंह मझवार, राजेंद्र सिंह सोनगिरा, कांचीसिंह सौंधिया, प्रमोद सक्सेना, मनोज गौतम, छगनलाल यादव, बाबा उपाध्याय, नरेंद्र साहू, अमरसिंह वर्मा, शौकत अली, केएम दांगी, षिवप्रताप विष्वकर्मा सहित अन्य ने मांग की है कि शिक्षकों सहित शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा योजना का लाभ मिलना चाहिए।

शिक्षकों की दिनांकवार हुई मृत्यु

दिनांक	मृत शिक्षक	दिनांक	मृत शिक्षक
20 अप्रैल	02	25 अप्रैल	02
21 अप्रैल	06	26 अप्रैल	02
22 अप्रैल	02	27 अप्रैल	03
23 अप्रैल	04	28 अप्रैल	05

कोई आदेश नहीं आए हैं

शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाना चाहिए। जो शिक्षक कोरोना महामारी से दिवंगत हो चुके हैं उनके परिवार को शासन द्वारा दी जाने वाली मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना का लाभ दिया जाए।

भरत गोयल,
प्रांतीय कोषाध्यक्ष, मप्र शासकीय अध्यापक संगठन

जैसे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, रोजगार सहायकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा माना गया है वैसे ही शिक्षा विभाग के लिए भी आदेश जारी होना चाहिए। हम शासन से यह मांग करते हैं क्योंकि शिक्षकों की ड्यूटी भी सर्वे एवं कोरोना से संबंधित अन्य कार्यों में लगाना शुरू हो चुकी है।

चंदर सिंह तोमर,
जिलाध्यक्ष, प्रांतीय शिक्षक संघ, राजगढ़

जब अधिकतर विभागों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित किया जा चुका है तो फिर शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो कि कोरोना से संबंधित ही ड्यूटी में लगे हैं उन्हें भी शासन को मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना का लाभ देना चाहिए। मैंने कल ही इस बारे में कलेक्टर साहब से भी बात की है।

भगवान राणावत,
जिलाध्यक्ष, रा. अध्यापक संगठन, राजगढ़

फिलहाल तक तो शिक्षा विभाग से मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना के संबंध में कोई आदेश नहीं आए हैं। आने पर उनका पालन किया जाएगा।

आरपी खिसरिया,
डीईओ, राजगढ़

अतिथि विद्वानों को कोरोना वॉलियंटर्स बनाने की मांग

पीपुल्स संवाददाता • ग्वालियर

editor@peoplessamachar.co.in

शासकीय कॉलेजों में सेवाएं देने वाले 450 से अधिक अतिथि विद्वान 17 महीने से बेरोजगार हैं। आर्थिक स्थिति बिगड़ने से घर चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार अतिथि विद्वानों के बारे में नहीं सोच रही है। कई अतिथि विद्वान चिंता में काल के गाल में समा चुके हैं।

अतिथि विद्वान नियमितिकरण संघर्ष मोर्चा ने सीएम को पत्र लिखा

अतिथि विद्वान नियमितिकरण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिह भदौरिया ने फॉलेन आउट अतिथि शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना वॉलियंटर की डिमांड की जा रही है। फॉलेट आउट अतिथि विद्वान इस मुश्किल घड़ी में वॉलियंटर्स बनने को तैयार हैं।

मानसिक तौर पर हताश और निराश हो चुके हैं

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिह ने पत्र में कहा है कि फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों को नियमिति करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, इससे अतिथि विद्वान हताश और निराश है मगर इसके बाद भी वह कोरोना संक्रमण में मदद के लिए तैयार हैं।

केवल 100 गज के दायरे में हो गई शिक्षक की पूरी नौकरी

पीपुल्स संवाददाता ● भिण्ड
editor@peoplessamachar.co.in

जिले के गोहद विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत घमूरी के ग्राम सिनोर निवासी छविराम शर्मा पुत्र शिव नारायण शर्मा ने अपनी पूरी नौकरी महज 100 गज के दायरे में पूरी कर ली। दर्जन भर शिकायतों के बाद भी शिक्षक पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नही की गई।

जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय बंद पाए जाने पर 16अप्रैल को समस्त स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यहां ये बताना आवश्यक है कि बेशक विद्यालय बच्चों के लिए बंद हैं, परंतु स्टाफ को निर्धारित समय अनुसार विद्यालय में

● दर्जन भर शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

उपस्थित रहने के आदेश हैं। लेकिन छविराम शर्मा केवल अपनी मर्जी से नौकरी कर सरकारी पगार प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल उक्त शिक्षक पर सरकारी हेडपंप पर कब्जा कर उसमे सबमर्सिबल मोटर डालकर निजी उपयोग में लेने का मामला सामने आया है, जिससे आस पास के रहवासियों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की शिकायत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता से की गई है। उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग गोहद के अधिकारी ने मौ थाना प्रभारी एवं एसडीएम गोहद को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से हेडपंप को अतिक्रमण मुक्त कराने को लिखा है। लेकिन आज तक इस मामले में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा निवासी ग्राम सिनोर जनपद गोहद ने इस मामले में शिक्षक की शिकायत की थी।

37 साल पहले हुई थी सिनोर में पोस्टिग

बीटीआईभिण्ड से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छविराम शर्मा की पहली पोस्टिंग 28 अगस्त 1984 को गृह ग्राम सिनोर गोहद में हुई थी। उसके बाद 17अप्रैल 2013 को प्रमोशन हुआ तो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय छैंकुरी में पोस्टिंग कर दी गई। अब तक कई शिकायतें हो चुकी हैं। इतना ही नहीं उक्त शिक्षक पर नौकरी और मेडिकल का एक साथ दोहरा लाभ लेने के आरोप भी लगाए गये है। लेकिन शिक्षक पर कोई कार्रवाई विभाग नहीं कर सका।

वैक्सीनेशन केंद्र पर कार्य करने वाले शिक्षकों ने की कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग

पीपुल्स संवाददाता ● सीहोर
मो.नं. 9425008066

प्रांतीय शिक्षक संघ ने सर्वे एवं वैक्सीनेशन के लिए कार्य कर रहे शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है। नसरुल्लागंज में प्रांतीय शिक्षक संघ के संगठन मंत्री बलराम पंवार के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया।

प्रांतीय शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश महासचिव सतीश त्यागी ने बताया की शिक्षकों से सीहोर जिले और प्रदेश सहित सभी जिलों में कोराना कार्य में ड्यूटी लगाई जा रही है। जबकि उसके साथ दल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकता कोरोना वारियर्स हैं, लेकिन शिक्षकों की बारी आती हैं तो केवल ड्यूटी। बाकी सब बाद में। अध्यापकों शिक्षक की मौत होने पर परिवार अनाथ, रातों रात घर से बेघर और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। इसी को लेकर शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग प्रांतीय शिक्षक संघ मप्र ने की है। मांग करने वालों में सतीश त्यागी, संजय, बलराम, राजेंद्र, प्रदीप सहित अनेक शिक्षक शामिल हैं।

दिसंबर माह से छात्र-छात्राओं को नहीं मिला सूखा राशन, आवंटन पर रोक

स्कूलों में 2 लाख 10 हजार बच्चों के एमडीएम की सुध भूली सरकार

पीपुल्स संवाददाता ● टीकमगढ़
मो.नं. 9691939149

कोरोना संक्रमणकाल में स्कूली छात्र-छात्राओं को मिलने वाले सूखा राशन की व्यवस्था एक बार फिर गड़बड़ा गई है। जिले में पिछले दिसंबर माह से बच्चों को राशन नहीं मिला है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शासन स्तर से ही आवंटन पर रोक लगा दी गई हैं। विदित है कि कोरोना संक्रमण के चलते शासकीय स्कूल बंद है। इसमें कोई भी बच्चा मध्याह्न भोजन से वंचित न रहे, इसके लिए बच्चों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी। किंतु बच्चों के प्रति सरकार व प्रशासन सुध नहीं ले रहा है।

जिले में एक हजार से अधिक समूहों द्वारा आंगनबाड़ियों के साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण किया जा रहा था। कोरोना वायरस से स्कूल बंद कर चल रहे हैं। शासन ने समूह संचालकों को मध्याह्न भोजन की जगह सूखा राशन वितरण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन जिले में दिसम्बर माह से प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के करीब 2 लाख 10 हजार छात्र-छात्राओं को सूखा राशन नहीं मिल रहा है। कोरोना

फाईलफोटो।

काल में प्रदेश सरकार ने स्कूल बंद होने पर अप्रैल से जुलाई तक बच्चों के खाते में खाना पकाने की राशि को दिया जा रहा था। इसमें प्राथमिक स्कूल के हर बच्चे प्रतिदिन के हिसाब से 4.97 रुपए और माध्यमिक स्कूल के हर बच्चे को 7.45 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाना बताया। इसके बाद राज्य शासन ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत स्कूल के बच्चों को सूखा राशन देने का निर्णय लिया। जुलाई माह से लगातार स्कूली बच्चों को सूखा राशन दिया जा रहा था, लेकिन पिछले पांच माह से राशन देना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर से ही आवंटन रुका हुआ है। वहीं राशन मुहैया होने को लेकर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल रहा है।

नवंबर तक मिला राशन

विभागीय जानकारी अनुसार प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूल के बच्चों को सूखा राशन दिया जा रहा था। इसमें प्राथमिक स्कूल के हर बच्चे को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 100 ग्राम एवं प्राथमिक स्कूल के हर बच्चे को 150 ग्राम हर दिन के हिसाब से देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद जुलाई से नवंबर तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के बच्चों को सूखा राशन दिया गया। इसमें प्राथमिक स्कूल के हर बच्चे को हर दिन के हिसाब से 100 ग्राम सूखा राशन तथा तीन माह का दो किलो दाल एवं 525 ग्राम तेल दिया गया। मिडिल स्कूल के हर बच्चे 150 ग्राम प्रतिदिन सूखा राशन एवं तीन माह का तीन किलो दाल एवं 738 ग्राम तेल दिया गया। किन्तु शासन अब बच्चों को एमडीएम मुहैया नहीं करा पा रही है। निवाड़ी और टीकमगढ़ में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल 2311 है। स्कूलों में 2 लाख 10 हजार के करीब बच्चें दर्ज है।

जिपं से मिलेगी जानकारी

इसकी जानकारी जिला पंचायत से मिलेगी।

– हनुमंत सिंह चौहान,
डीपीसी, टीकमगढ़

बड़वानी जिले के अजराड़ा गांव में प्रशासन की कार्रवाई

शादी में पहुंचे 300 लोग, शिक्षक व सचिव को हटाया, सरपंच को पद से अलग किया

पीपुल्स ब्यूरो • बड़वानी
मो.नं. 9425088883

जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने ग्राम अजराड़ा में एक वैवाहिक समारोह में निर्धारित संख्या का उल्लंघन कर 300 लोगों के शामिल होने पर प्राथमिक शिक्षक और ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। इसके अलावा सरपंच को पद से पृथक करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर वर्मा ने 26 अप्रैल को यहां ग्राम अंजराणा में एक वैवाहिक समारोह में 300 लोगों के भाग लेने पर आयोजनकर्ता प्राथमिक शिक्षक गुमान सिंह को निलंबित कर दिया है। वहीं कर्तव्य निर्वहन नहीं करने पर ग्राम पंचायत सचिव संतोष धनगर को भी निलंबित कर दिया है। साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋतुराज सिंह को ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक सुखलाल गुसाई एवं सरपंच वाहरिया को पद से अलग कर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

अभाली गांव सील नहीं किया, सचिव, सरपंच पर कार्रवाई

कलेक्टर ने जिले के ग्राम अभाली में कोरोना पॉजीटिव मामले पाए जाने के बाद भी ग्राम को सील नही करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच को पद से अलग करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बड़वानी जिले में फिलहाल 847 कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। अभी तक बड़वानी जिले में 6,673 लोग पॉजीटिव पाए गए, जिसमें से 5,589 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में अब तक 48 लोगों की मौत हुई है।

आलीराजपुर जिले का मामला

विवाह में डीजे पर नाच रहे दूल्हा दुल्हन सहित सात पर कार्रवाई

जिले में कोरोना के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर दुल्हा-दुल्हन और ग्राम सरपंच सहित सात लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आलीराजपुर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद जिले के चन्द्रशेखर आजाद नगर जनपद क्षेत्र के ग्राम छोटा खुटाजा में आयोजित एक विवाह कार्यक्रम में डीजे के साथ करीब 150 से 200 लोगों को एकत्र होने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में सात लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई में दला अजनार, रूपली अजनार निवासी छोटा खुटाजा, विकेश बामनिया निवासी संदा, चेनिया बामनिया निवासी संदा, डीजे मालिक रमेश निवासी ग्राम छोटा खुटाजा, ग्राम पंचायत छोटा खुटाजा सरपंच मदन मावी और चौकीदार सुरेश मावी पर भादवि की धाराओं, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं और म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

यह है मामला

उल्लेखनीय है कि ग्राम छोटा खुटाजा में दुल्हा-दुल्हन करीब 150 से 200 बारातियों के साथ विवाह कार्यक्रम में डीजे पर नाच रहे थे। इस विवाह कार्यक्रम के संबंध में ग्राम सरपंच और चौकीदार द्वारा प्रशासन को जानकारी उपलब्ध नही कराई गई। जिस पर संबंधितों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

सीबीएसई : नई शिक्षा नीति के तहत किया गया बदलाव

9वीं से 12वीं तक का एग्जाम पैटर्न बदला छात्रों की सोचने की क्षमता परखेंगे

भास्कर न्यूज | इंदौर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा सत्र 2021-22 से नौवीं से 12वीं के परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव इसी सत्र से लागू होगा। अब परीक्षा में दसवीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अब लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 फीसदी कम पूछे जाएंगे। यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये प्रश्न बहुविकल्पीय, केस-आधारित या अन्य किसी रूप में हो सकते हैं। इसका मकसद छात्रों की सोचने की क्षमता को बढ़ाना और बेहतर बनाना है। नए बदलाव के बाद 9वीं और 10वीं बोर्ड में 30% और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में 20% क्षमता आधारित प्रश्न रहेंगे। अभी तक क्षमता बेस्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते थे।

नए पैटर्न पर जारी होगा सैंपल पेपर : बोर्ड के एकेडेमिक डायरेक्टर डा. जोसफ इमैनुअल के अनुसार बदले हुए नए पैटर्न पर सैंपल पेपर जारी किए जाएंगे। स्कूलों को इसी पैटर्न पर पढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है।

9वीं और 10वीं में

- क्षमता बेस्ड प्रश्न 30% रहेगा। (इसमें मल्टीपल च्वाइस, केस स्टडी, इंटीग्रेटेड प्रकार के प्रश्न रहेगा)
- 20% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा।
- लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 60% से घटा कर अब 50% पूछे जाएंगे।

11वीं और 12वीं में

- क्षमता बेस्ड 20% प्रश्न रहेगा। (इसमें केस स्टडी, मल्टीपल च्वाइस, इंटीग्रेटेड प्रकार के प्रश्न रहेगा)
- 20% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा
- लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब 70% से घटा कर 60% कर दिया गया है।

10वीं-12वीं के प्रवेश-पत्रों में 10 तक संशोधन

शिवपुरी | माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल, हायर सेकंडरी, हायर सेकंडरी वोकेशनल और अन्य परीक्षाओं के प्रवेश-पत्रों में अब विद्यार्थी 10 मई तक संशोधन करा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 15 अप्रैल निर्धारित थी। कोविड 19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश-पत्र में संशोधन करने की अवधि में वृद्धि की गई है। सभी संस्था प्राचार्य, परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर व पद मुद्रा अंकित कर छात्रों को उपलब्ध कराएंगे।

वैक्सीन बनी जानलेवा, शिक्षक ने तोड़ा दम

शिवपुरी के जामखो प्रावि में पदस्थ सहायक शिक्षक कैलाश नारायण शर्मा की बुधवार को एकाएक बिगड़ी हालत के चलते अस्पताल ले जाने से पूर्व ही मौत हो गई। बताया जाता है कि शिक्षक को हाल ही में वैक्सीन का दूसरा टीका भी लग गया था। पर वैक्सीनेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ी, उन्हें उल्टी हुई और जकड़न की शिकायत पर परिजन अस्पताल ले जाते, उससे पूर्व ही उन्होंने दम तोड़ दिया।मंगलवार तक वह एकदम स्वथ्य थे। यहां बता दें कि करई में पदस्थ शिक्षक पंकज श्रीवास्तव निवासी विवेकानंदपुरम ने मंगलवार को ठीक इसी तरह से दम तोड़ दिया। उनकी अंत्येष्टि पंकज की बेटी ने की।

तीन मई तक के लिए रिसर्च स्कॉलर भी हुए निश्चिंत

कोरोना कर्फ्यू: घरों पर रिसर्च पेपर तैयार कर रहे प्रोफेसर्स

कोरोना कर्फ्यू में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय साहित सूबे के कॉलेजों में पदस्थ प्रोफेसर रिसर्च पेपर लिखने में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। क्योंकि उन्हें रिसर्च पेपर पर कार्य करने पर्याप्त समय मिल रहा है। यही स्थिति राज्य के अन्य विवि के प्रोफेसरों की भी है। वह भी कोरोना कर्फ्यू में मिलने समय का पूरा उपयोग अपने रिसर्च वर्क को पूरा करने में लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि गत वर्ष की तरह सरकार कर्फ्यू को 15 मई तक ले जाएगी।

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रदेशभर की शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा अन्य कार्य बंद हैं। इसलिए प्रोफेसरों के पास काफी वक्त मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने अपने खाली वक्त का उपयोग रिसर्च वर्क में करना शुरू कर दिया है।

दस दिन के लॉकडाउन में मिले समय में उन्होंने काफी हद तक अपना रिसर्च वर्क पूरा किया है। कुछ प्रोफेसरों का कहना है कि अभी कोराना कर्फ्यू खत्म होने में लंबा समय लग सकता है। इस दौरान उनका रिसर्च वर्क पूरा हो जाएगा।

वहीं, कुछ का पचास फीसदी रिसर्च वर्क पूरा होगा। कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद रिसर्चवर्क पूरा होने पर वे अपने रिसर्च पेपर प्रकाशित कराएंगे। वर्तमान में राज्य में करीब पांच हजार प्रोफेसर हैं, जो कोरोना कर्फ्यू के कारण अपने घरों में ठहरे हुए हैं। वे अपने कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग कर रिसर्च वर्क में जुट गए हैं। पांच मई तक कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद प्रदेश से काफी संख्या में रिसर्च पेपर प्रकाशित होने के कयास लगाए जा रहे हैं।

स्कॉलर भी कर रहे फोकस

अपने गाइड को रिसर्च कार्य में व्यस्त देख रिसर्च स्कॉलर भी अपने रिसर्च पर फोकस करने लगे हैं। जरूरत होने पर वे अपने गाइड या को-गाइड को मोबाइल या वीडियो कॉल कर रिसर्च से संबंधित अपडेट ले रहे हैं। इससे उनकी रिसर्च वर्क में कोरोना कर्फ्यू कोई समस्या खड़ी नहीं कर पा रहा है। वे भी तीन मई तक कर्फ्यू बढ़ने से निश्चिंत हो गए हैं।

प्रदेश टुडे एजुकेशन

फिर नहीं मिलेगा समय

प्रोफेसरों का कहना है उनका पूरा दिन कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक व कार्यलायीन में निकल जाता है। इस बीच रिसर्च के लिए वक्त निकालने में काफी समयस्या होती है। वर्तमान में उनके पास 24 घंटे मौजूद हैं। इसके कारण वे अपना पूरा समय अपनी लैब और पुराने रिसर्च पेपर को पढ़ने में लगा रहे हैं।

बीयू प्रोफेसरों के अच्छे प्रोजेक्ट पर दो लाख रुपए तक की वित्तीय मदद करेगा। कोरोना कर्फ्यू से काफी गतिविधियां बंद हैं, जिसका फायदा प्रोफेसर अपना रिसर्च वर्क पूरा करने में उठा रहे हैं। – डॉ. हरिहर शरण त्रिपाठी, रजिस्ट्रार

कोरोना **विश्वविद्यालय बंद होने के चलते परीक्षा से जुड़े कई कार्य हो रहे हैं प्रभावित**

स्नातक की ओपन बुक परीक्षाओं में डाला खलल

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कॉलेजों में स्नातक स्तर की परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति के माध्यम से आयोजित कराई जानी हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को मई में परीक्षा करवाने की तारीख भी तय की हुई है लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव ने इस प्रक्रिया में रोड़ा खड़ा कर दिया है। लगातार लाकडाउन बढ़ने के कारण परीक्षाओं की तैयारी अटकी हुई है। परीक्षाओं को लेकर शासन स्तर पर नई गाइड लाइन जारी न होने तो वहीं परीक्षा से जुड़े कई काम अब तक शुरू न हो पाने के चलते रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन भी परेशान है।

50 हजार विद्यार्थियों की होनी है परीक्षाएं : बताया जाता है स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में करीब 50 हजार छात्र अध्ययनरत हैं। सर्वाधिक छात्र प्रथम वर्ष में करीब 30 हजार हैं। इन सभी छात्रों की परीक्षाएं इस बार ओपन बुक पद्धति के माध्यम से कराई जानी हैं। पिछले वर्ष यह परीक्षाएं सितंबर-अक्टूबर में आयोजित की गई थी। परीक्षाएं कराने में ही विश्वविद्यालय को करीब 15 दिन लगेंगे।

कियोस्क बंद होने से परेशानी : गौरतलब है कि कियोस्क सेंटर बंद होने के कारण सर्वाधिक परेशानी खड़ी हुई है। क्योंकि इस बार नामांकन प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण कई छात्र नामांकन भर नहीं सके थे। जब नामांकन भरने की लिंक खोली गई तो लाकडाउन लग गया। आनलाइन सेंटर बंद रहने के कारण भी कई छात्र परीक्षा आवेदन नहीं भर सके। सबसे ज्यादा तकनीकी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों दूरस्थ जिलों में रहने वाले छात्रों को उठानी पड़ी है। विवि से जुड़े करीब 160 से अधिक कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाएं करानी हैं।

> लाकडाउन लगने के कारण परीक्षा से जुड़ी गतिविधियां प्रभावित हुई है। मई में परीक्षाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। फिर भी हमने प्रश्न पत्र पहले से ही तैयार कर रखे है। शासन से नए आदेश का हम इंतजार कर रहे है।
>
> **- प्रो.एनजी पेंडसे**, परीक्षा नियंत्रक

शासकीय कॉलेजों में बाजार की जरूरत के हिसाब से कोर्स शुरू होंगे

- उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 100 कॉलेजों को चुना है, अंचल के कई कॉलेज शामिल

पीपुल्स संवाददाता • ग्वालियर

editor@peoplessamachar.co.in

प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब बाजार की जरूरत के हिसाब से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके पीछे मकसद यह है कि कोर्स करने वाले छात्रों को जॉब आसानी से मिल सके।

उच्च शिक्षा विभाग ने बाजार की जरूरत के हिसाब से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए प्रदेश के 100 शासकीय कॉलेजों को चुना है, इनमें कई कॉलेज ग्वालियर चंबल संभाग के शामिल हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ही जॉब ओरिन्टेड कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। विभाग ने कॉलेजों को अपने स्तर पर कोर्स डिजाइन करने की परमिशन दे दी है। कॉलेज अपने क्षेत्र के बाजार का अध्ययन करके ऐसे कोर्स डिजाइन करेंगे, जिन्हें करने के बाद छात्रों को आसानी से रोजगार मिल सके।

कॉलेजों में पहले से चल रहे जॉब ओरिन्टेड कोर्स

शहर के केआरजी कॉलेज सहित कई गवर्मेंट कॉलेजों में पहले से जॉब ओरिन्टेंड कोर्स संचालित हो रहे हैं। इन कोर्सों में छात्र बड़ी संख्या में प्रवेश ले रहे हैं। कोर्स करने के बाद छात्र स्वयं का रोजगार शुरू कर दिया है।

इनका कहना है

प्रदेश के 100 गवर्मेंट कॉलेजों में बाजार की जरूरत के हिसाब से डिप्लोमा-सर्टिफिकेट शुरू होंगे। 100 कॉलेजों की सूची में अंचल के कई कॉलेज शामिल हैं। कोर्स करने के बाद छात्रों को आसानी से रोजगार मिल सकेगा।

प्रो. एमआर कौशल, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग

ड्यूटी में लापवाही पर 4 सहा प्राध्यापकों को नोटिस जारी

पीपुल्स संवाददाता ● दमोह

मो.नं. 8435502322

विधानसभा उपनिर्वाचन 2021 हेतु विधानसभा क्षेत्र 55 दमोह की मतगणना प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर सरकारी कॉलेज जबेरा के सहायक प्राध्यापक अमितेष सोनी एवं सरकारी कॉलेज हटा के सहायक प्राध्यापक प्रशांत सूर्यवंशी, मनोज सिंह गुर्जर और राहुल चौधरी को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन्हें 27 अप्रैल को प्रशिक्षण प्राप्त करने आदेशित किया गया था, लेकिन ये अनुपस्थित रहे।

नोटिस में लिखा गया गई कि यह कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व नियम 1950 का स्पष्ट उल्लंघन होकर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को प्रकट करता है जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, क्यों न मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)-1966 के तहत दंडित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाए। इस संबंध में इनसे 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। ज्ञातव्य हो कि चुनाव संबंधी कार्य आवश्यक और अनिवार्य सेवा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। पूर्व में यहां के प्रभारी प्राचार्य सूरज प्रसाद पचौरी की कार्यपद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं।

वहीं हटा के प्रभारी प्राचार्य पीके ढाका को एक सहायक प्राध्यापक के अस्वस्थ होने की जानकारी तो है। लेकिन अन्य दो के अनुपस्थित होने का स्पष्ट जबाव नहीं है।

कॉलेजों की फीस तय नहीं फिर होगी मनमानी वसूली

उच्च शिक्षा विभाग ने 2019 में विवि को दी जिम्मेदारी

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया जून-जुलाई में होगी। लेकिन फीस को लेकर असंमजस है। ऐसे में नए विद्यार्थियों को कॉलेज डिसाइड करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

शासन ने कॉलेजों की फीस तय करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को दी है। विश्वविद्यालयों ने 28 दिसंबर 2019 को बैठक में सेंट्रल कमेटी गठित कर कॉलेजों की फीस तय करने का निर्णय लिया था। कमेटी का गठन विवि को करना था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि आधी-अधूरी कमेटी बनी है।

प्रवेश प्रक्रिया में दो माह शेष अभी प्रपोजल तक तैयार नहीं

प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने में दो माह बचे हैं। नियम बनाने के बाद निजी कॉलेज फीस निर्धारण के संबंध में संबंधित विवि को प्रपोजल देंगे। यह प्रपोजल विभिन्न पाठ्यक्रमों के आधार पर अलग-अलग होगा। इसके बाद विवि फीस तय करेगा। कोरोना संक्रमण के कारण यह मामला अटका हुआ है।

विवि और संबद्ध कॉलेज

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल	386
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	250
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर	167
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर	178
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा	127
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन	101

कॉलेजों में सुविधा के हिसाब से तय करनी थी फीस

विश्वविद्यालयों को संबद्ध कॉलेजों की सुविधाओं और छात्र संख्या के हिसाब से फीस तय करनी थी। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही वर्चुअल बैठक होनी है। इसमें फीस निर्धारण को लेकर चर्चा की जाएगी। पारंपरिक विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी कॉलेजों में चलने वाले बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम आदि की फीस तय करने का अधिकार अब तक सरकारी नोडल कॉलेजों को था, इस साल से शासन ने यह अधिकार भी विवि को दे दिया है।

कुलपति की अध्यक्षता में बनाई है कमेटी, जल्द होगी बैठक

कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। इसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के तीन-तीन प्राचार्यों को मेंबर बनाया गया है। शीघ्र ही कमेटी की बैठक कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. एच.एस. त्रिपाठी, रजिस्ट्रार, बीयू२

वन विभाग ने शुरू की तबादला सूची बनाने की कवायद

सर्कल्स से मांगी कर्मचारियों की डिटेल

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल

मो.नं. 9425018933

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जहां सरकारी दफ्तरों में अधिकारी-कर्मचारी दहशत में है, वहीं वन विभाग में तबादला सूची तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यालय ने सभी सर्कल्स से तीन साल से पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी बुलाई है।

प्रदेश में एक मई तक लगी तबादला सूची पर लगी रोक हटने जा रही है। इसके बाद तबादले भी शुरू हो जाएंगे। इधर, सरकारी दफ्तरों में कोरोना के कारण 10 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के आदेश भी सामान्य प्रशासन विभाग जारी का चुका है। इस आदेश के चलते दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या सिमट गई है और वे सूने पड़े हैं। इस बीच वन मुख्यालय की प्रशासन शाखा-2 ने सभी 16 मुख्य वन (सीसीएफ) को पत्र भेजकर वन क्षेत्रपाल और उपवन क्षेत्रपाल स्तर के कर्मचारी जो एक ही कार्यालय में तीन साल की अवधि से ज्यादा समय से पदस्थ हैं, की जानकारी मांगी है। इसके अलावा लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू एवं अन्य गंभीर अनुशासनहीनता की शिकायतें लंबित हैं और जिन्होंने स्वेच्छा से तबादलों के लिए आवेदन किया है, उनकी भी जानकारी तीन दिन में मांगी गई है। सूत्रों का कहना है कि 10 सर्कल ने यह जानकारी भेज दी है। बचे हुए छह सर्कल को इस जानकारी के लिए रिमांडर भेजा गया है।

एंटीबॉडी मिलने का अर्थ ये नहीं कि आपको दोबारा संक्रमण नहीं होगा, लापरवाही बरतना खतरनाक

भास्कर नॉलेज सीरीज विशेषज्ञ बोले-सीटी स्कैन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करवाएं

• कोरोना की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है? कौन से लक्षण दिखें तो ये टेस्ट करवाना चाहिए?

पूरे विश्व में आज भी कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए सबसे विश्वनीय आरटी-पीसीआर जांच ही है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, सिर में दर्द, डायरिया, कंजेक्टिवाइटिस और थकान। इसके अलावा यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों तो लक्षण न दिखने पर भी पांच दिन बाद जांच करानी चाहिए। लक्षण दिखने के बाद भी यदि जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है तो एक से दो दिनों बाद दोबारा जांच करानी चाहिए। क्योंकि लक्षण के बाद भी निगेटिव रिपोर्ट आने के कई कारण हो सकते हैं।

• क्या संक्रमण की बेहतर पहचान के लिए किसी और टेस्ट पर भी काम हो रहा है?

कोरोना की दवा और वैक्सीन से लेकर जांच किट पर भी पूरे विश्व में काम हो रहा है लेकिन अभी आरटी-पीसीआर का प्रभावी विकल्प नहीं है।

• बिना कोरोना की पहचान का टेस्ट करवाए क्या कोई एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकता है? यदि टेस्ट में एंटीबॉडी मिलें तो क्या इसका अर्थ है कि व्यक्ति संक्रमित होकर ठीक हो चुका है?

यदि शरीर में एंटीबॉडी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि संक्रमण पहले हुआ होगा। लेकिन एंटीबॉडी है इसका अर्थ यह नहीं है कि दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है। आज के समय में कोई भी एंटीबॉडी जांच बहुत प्रभावी नहीं है। लिहाजा बतौर विशेषज्ञ एंटीबॉडी जांच की सलाह नहीं दे सकता।

• संक्रमण का पता चलने के बाद भी सिर्फ लक्षणों से इसके माइल्ड या गंभीर होने का पता चल जाता है या फिर कोई टेस्ट कर इसका पता किया जा सकता है?

जांच से सिर्फ संक्रमण का पता चलता है। इसके बाद लक्षण और चिकित्सीय समझ के आधार पर अनुमान लगा कर मरीज की वर्तमान स्थिति के साथ मरीज के स्वास्थ्य में किस तरह का बदलाव हो सकता है उसका इलाज किया जाता है।

• फेफड़ों में संक्रमण जांचने के लिए सीटी स्कैन की सलाह दी जाती है। सीटी स्कैन का स्कोर संक्रमण की गंभीरता कैसे बताता है?

फेफड़ों में संक्रमण की जांच के लिए गैर जरूरी सीटी स्कैन कराने के लिए भीड़ नहीं लगानी चाहिए। सीटी स्कैन डॉक्टर्स से बिना सलाह लिए न कराएं। लक्षण हो जांच रिपोर्ट निगेटिव हो तब भी सीटी स्कैन कराना चाहिए। फेफड़े में संक्रमण किस स्तर तक है यह डॉक्टर बता सकते हैं।

• संक्रमण से उबरने के बाद क्या एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए? ये एंटीबॉडी कितने दिन तक व्यक्ति को संक्रमण से बचा सकती हैं?

बतौर विशेषज्ञ एंटीबॉडी टेस्ट कराने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि बाजार में कोई भी एंटीबॉडी टेस्ट ऐसा नहीं है जो बहुत प्रभावी हो। एंटीबॉडी नहीं मिलने पर मरीज की परेशानी बढ़ जाती है जबकि एंटीबॉडी मिलने पर मरीज लापरवाह हो जाता है, जो सही तरीका नहीं है।

दैनिक भास्कर भोपाल 29-04-2021

18+ के टीकाकरण के लिए पहले ही दिन 1.33 करोड़ रजिस्ट्रेशन

लोग तैयार, टीका तो दीजिए सरकार

- शुरुआती दो घंटे में ही कोविन पोर्टल पर 5 करोड़ लोग पहुंचे
- दिन में रही परेशानी, किसी को स्लॉट तो किसी को सेंटर का पता नहीं

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

कोविन पोर्टल पर बुधवार शाम 4 बजे से 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। पहले दिन 1.33 करोड़ लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि आगाज के साथ ही इस अभियान को कई हिचकोले भी लगे। पहले दो घंटे में 5 करोड़ लोग Cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए। कई बार सर्वर जाम होने से परेशानी आई। शाम 7 बजे तक 79.65 लाख रजिस्ट्रेशन हो सके थे। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ भी उनमें से कई लोगों को टीकाकरण की तारीख नहीं बताई गई। कई को मई के बजाय अगस्त की तारीख मिली। कई को ये नहीं बताया गया कि उन्हें किस सेंटर पर कौन सी वैक्सीन मिलेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि कई राज्यों ने अभी सेंटर्स की सूची, वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी नहीं दी है।

सीरम अब राज्यों को 400 के बजाय 300 रु. में देगा एक डोज

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का दाम 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए प्रति डोज कर दिया है। हालांकि यह अब भी केंद्र के लिए तय कीमत 150 रुपए प्रति डोज से दोगुना है।

भास्कर पड़ताल : राज्यों ने वैक्सीन कंपनियों को ऑर्डर तो कर दिए, मगर कीमतों पर संशय के चलते नहीं जानते खेप कब तक मिलेगी

राज्यों ने 1 मई से टीकाकरण अभियान के लिए कंपनियों को ऑर्डर तो दिए हैं, मगर अभी यह साफ नहीं है कि कंपनी की ओर से घोषित कीमत पर ही वैक्सीन मिलेगी या राज्यों की कीमतें घटाने की मांग पर कोई कदम उठाया जाएगा। यही नहीं, जो ऑर्डर किए गए हैं वह कंपनियां कब तक डिलीवर करेंगी ये भी स्पष्ट नहीं है। जानिए, बड़े राज्यों की क्या है स्थिति-

उत्तर प्रदेश : 18 से 44 वर्ष के लोगों की आबादी 9.15 करोड़ है। सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। मगर यह टुकड़ों में आएगा। तिथि तय नहीं है।

झारखंड : 18 से 44 वर्ष के लोगों की आबादी 1.57 करोड़ है। सरकार ने 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। मिलने का समय तय नहीं।

गुजरात : 18 से 44 वर्ष के लोगों की आबादी 3.25 करोड़ है। सरकार ने 1.50 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। मिलने का समय तय नहीं।

राजस्थान : 18 से 44 वर्ष के लोगों की आबादी 3.5 करोड़ है। सरकार ने 3.75 करोड़ डोज का ऑर्डर सीरम को दिया। मंत्री भी कह चुके-1 मई को मिलना मुश्किल।

छत्तीसगढ़ : 18 से 44 वर्ष के लोगों की आबादी 1.20 करोड़ है। सरकार ने 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। मिलने का समय तय नहीं है।

महाराष्ट्र को 20 मई तक वैक्सीन नहीं दे पाएंगी कंपनियां, बिहार को देने में असमर्थता जता दी

मुंबई में 45+ के लिए भी 47 हजार वाइल का ही स्टॉक, गुरुवार को नहीं होगा टीकाकरण

मुंबई में वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं होने की वजह से गुरुवार को 73 में से 40 केंद्रों पर टीकाकरण नहीं होगा। बाकी 33 प्राइवेट केंद्र पर भी दूसरे डोज वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुंबई में बुधवार की दोपहर 2 बजे तक ही टीका लगा। उसके बाद सिर्फ 47,740 वायल्स का स्टॉक बचा था।

महाराष्ट्र : 18 से 44 वर्ष के लोगों की आबादी 5.71 करोड़ है। सरकार ने करीब 1.30 करोड़ डोज का ऑर्डर दोनों कंपनियों को दिया है। मगर दोनों ने ही 20 मई से पहले देने में असमर्थता जता दी है।

बिहार : 18 से 44 वर्ष के लोगों की आबादी 5.47 करोड़ है। सरकार ने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर सीरम को दिया। कंपनी ने डिलीवरी में असमर्थता जताई है।

डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में बनी सहमति

अस्पताल में भर्ती मरीज का आधार लिंक करें, ताकि पता चले कि कौन सी दवा दी

हेल्थ रिपोर्टर | भोपाल

अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों का आधार लिंक किया जाए ताकि उनके परिजनों को पता चल सके कि मरीज को कौन सी दवा दी गई और जिनकी फीस ली गई है वह सही है या नहीं। इससे अस्पतालों की मनमानी रुकेगी। इसी के साथ सात दिन बेहद सख्ती के साथ पहले जैसा लॉकडाउन लगाया जाए। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद किए जाएं। बुधवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सदस्यों ने इस संबंध में अपनी सहमति दी।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि निजी अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों को दवा और ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ता है। जब रजिस्ट्री मे आधार लिंक हो सकता है तो फिर भर्ती होने पर भी हो सकता है। इससे निजी अस्पतालों की मनमानी रुकेगी।

कलेक्टर और डीआईजी सड़क पर उतरे, पूछताछ की

कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली ने रोशनपुरा चौराहे पर बेवजह घूमने वालों से पूछताछ की और जेल वाहन में बैठा दिया। लवानिया ने बताया कि इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई।

सख्ती हो, 7 दिन के लिए बंद हों सरकारी और निजी संस्थान

विधायक विष्णु खत्री, कृष्णा गौर ने कहा कि जिस तरह की सख्ती पिछले साल लॉकडाउन में थी, वैसी ही अब भी होना चाहिए तभी स्थिति नियंत्रित हो पाएगी। इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर सरकारी दफ्तर, निजी संस्थान 7 दिन के लिए पूरी तरह बंद किए जाएं। बैठक में सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी पर भी सदस्यों ने नाराजगी जताई। उनसे कहा गया कि मरीज के परिजनों को उसके स्वास्थ्य की जानकारी दें।

अमेरिकी मदद • भारतवंशी सांसद, विशेषज्ञों ने कहा- दी जा रही मदद नाकाफी

भारत को यूएस से 1 करोड़ डोज संभव; विशेषज्ञ चाहते हैं दोगुनी मदद हो

न्यूयॉर्क से भास्कर के लिए
मोहम्मद अली

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की मदद के लिए वैक्सीन, रॉ मेटेरियल समेत अन्य उपकरण भारत भेजने की बात कही है। इस मदद को भारतीय अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने नाकाफी बताया है। इनका कहना है, भारत में महामारी की गंभीरता को देखते हुए, वर्तमान अमेरिकी सहायता पर्याप्त नहीं है। बाइडेन प्रशासन को 'भारत के लिए भेजे जाने वाली ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सप्लाई को दोगुना करना चाहिए।' साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि भारत में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण था कि बाइडेन प्रशासन इस संकट में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ा हो।

अमेरिका ने भारत समेत दूसरों देशों को 6 करोड़ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देने का वादा किया है। हालांकि, व्हाइट हाउस के अफसरों को अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी होगी। लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि इसमें 1 करोड़ वैक्सीन भारत भेजी जा सकती हैं। 5 करोड़ निर्माण प्रक्रिया में हैं और वो भी कुछ हफ्तों में दुनियाभर में भेज दी जाएंगी। दूसरी ओर, कई एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस अभूतपूर्व संकट के समय दुनिया को 6 करोड़ वैक्सीन भेजना नाकाफी है। हेल्थ गैप की एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर एशिया रसेल कहती हैं कि 6 करोड़ डोज देना वैसा ही है, जैसे आग बुझाने के लिए बूंद का इस्तेमाल किया जा रहा है।

एस्ट्राजेनेका को मंजूरी नहीं, फिर भी जरूरत से ज्यादा डोज खरीदीं

अमेरिका में लाखों एस्ट्राजेनेका बर्बाद, स्टोरेज में रखी वैक्सीन पर भी खतरा

यूएस में एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन जरूरत से 55 करोड़ डोज अधिक संग्रहित की जा चुकी हैं। संभवतः इसलिए बाइडेन से मांग की जा रही है कि यह वैक्सीन भारत भेजी जाए, क्योंकि वहां मंजूरी मिल चुकी। जल्द न भेजा गया तो वैक्सीन की शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी। प्रशासन के संज्ञान में जानकारी आई है कि अक्टूबर-जनवरी के बीच बनी लाखों डोज खराब होने से डर से फेंकी गईं। अभी स्टोरेज में रखी वैक्सीन जनवरी के बाद बनी है, जो जल्द खराब हो सकती है।

लाइसेंस लिए बिना दुनिया वैक्सीन की मांग को पूरा नहीं कर सकतेः रो खन्ना

सिलिकॉन वैली से सांसद रो खन्ना ने इस बात की सराहना की है कि वैक्सीन बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कानून में छूट देना एक सही कदम है, क्योंकि आने वाले समय में भारत और दुनिया के अन्य देश आयात करने के बजाय वैक्सीन खुद बना सकेंगे। लेकिन एक ही चीज जो बाकी रह गई है, वो फाइजर मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से वैक्सीन बनाने का लाइसेंस लेना, ताकि यह वैक्सीन भारत के साथ-साथ दुनिया के अन्य देशों में भी बनाई जा सके।

भारत में रह रहे प्रेमा जयपाल के पिता को देनी पड़ी ऑक्सीजन

प्रेमा जयपाल के ऑफिस ने बताया कि भारत में रह रहे उनके माता-पिता दूसरी लहर की शुरुआत में संक्रमित हुए थे, जो तेजी से ठीक हो रहे हैं। प्रेमा भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद हैं जो हाल में भारत माता-पिता को देखने आईं थीं। उनके पिता 90 और मां 80 वर्ष की हैं। दोनों संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए थे और उनके पिता को ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ी थी।

रूस से आज भारत आएगी मदद की पहली खेप और अमेरिका से कल तक

नई दिल्ली | कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए अमेरिकी सहायता की पहली खेप गुरुवार-शुक्रवार के बीच आएगी। भारत ने इससे पहले अमेरिका के साथ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खरीद और वैक्सीन के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का मुद्दा उठाया था। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने फोन पर कोरोना से पैदा हुए हालात पर चर्चा की है। उम्मीद है कि रूस से आने वाली मदद की पहली खेप भी आज आएगी।

डब्ल्यूएचओ का दावा- दुनिया के 17 देशों तक पहुंच गया है भारतीय वैरिएंट

भारत में कोरोना के तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण डबल म्यूटेंट बताया जा रहा है। लेकिन अब भारत का ये वैरिएंट दुनिया के कई देशों तक पहुंच चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ये जानकारी दी है। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि भारत का ये कोरोना म्यूटेंट दुनिया के करीब 17 देशों तक पहुंच चुका है। भारत के इस डबल म्यूटेंट को B.1.617 नाम दिया गया है। इस तरह का म्यूटेंट सबसे पहले भारत में मिला, इसीलिए इसे भारतीय म्यूटेंट कहा जा रहा है।

तीन मई तक के लिए रिसर्च स्कॉलर भी हुए निश्चिंत

कोरोना कर्फ्यू: घरों पर रिसर्च पेपर तैयार कर रहे प्रोफेसर्स

कोरोना कर्फ्यू में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय साहित सूबे के कॉलेजों में पदस्थ प्रोफेसर रिसर्च पेपर लिखने में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। क्योंकि उन्हें रिसर्च पेपर पर कार्य करने पर्याप्त समय मिल रहा है। यही स्थिति राज्य के अन्य विवि के प्रोफेसरों की भी है। वह भी कोरोना कर्फ्यू में मिलने समय का पूरा उपयोग अपने रिसर्च वर्क को पूरा करने में लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि गत वर्ष की तरह सरकार कर्फ्यू को 15 मई तक ले जाएगी।

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रदेशभर की शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा अन्य कार्य बंद हैं। इसलिए प्रोफेसरों के पास काफी वक्त मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने अपने खाली वक्त का उपयोग रिसर्च वर्क में करना शुरू कर दिया है।

दस दिन के लॉकडाउन में मिले समय में उन्होंने काफी हद तक अपना रिसर्च वर्क पूरा किया है। कुछ प्रोफेसरों का कहना है कि अभी कोरोना कर्फ्यू खत्म होने में लंबा समय लग सकता है। इस दौरान उनका रिसर्च वर्क पूरा हो जाएगा।

वहीं, कुछ का पचास फीसदी रिसर्च वर्क पूरा होगा। कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद रिसर्चवर्क पूरा होने पर वे अपने रिसर्च पेपर प्रकाशित कराएंगे। वर्तमान में राज्य में करीब पांच हजार प्रोफेसर हैं, जो कोरोना कर्फ्यू के कारण अपने घरों में ठहरे हुए हैं। वे अपने कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग कर रिसर्च वर्क में जुट गए हैं। पांच मई तक कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद प्रदेश से काफी संख्या में रिसर्च पेपर प्रकाशित होने के कयास लगाए जा रहे हैं।

स्कॉलर भी कर रहे फोकस

अपने गाइड को रिसर्च कार्य में व्यस्त देख रिसर्च स्कॉलर भी अपने रिसर्च पर फोकस करने लगे हैं। जरूरत होने पर वे अपने गाइड या को-गाइड को मोबाइल या वीडियो कॉल कर रिसर्च से संबंधित अपडेट ले रहे हैं। इससे उनकी रिसर्च वर्क में कोरोना कर्फ्यू कोई समस्या खड़ी नहीं कर पा रहा है। वे भी तीन मई तक कर्फ्यू खुलने से निश्चिंत हो गए हैं।

फिर नहीं मिलेगा समय

प्रोफेसरों का कहना है उनका पूरा दिन कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक व कार्यकलापों में निकल जाता है। इस बीच रिसर्च के लिए वक्त निकालने में काफी समस्या होती है। वर्तमान में उनके पास 24 घंटे मौजूद हैं। इसके कारण वे अपना पूरा समय अपनी लैब और पुराने रिसर्च पेपर को पढ़ने में लगा रहे हैं।

बीयू प्रोफेसरों के अच्छे प्रोजेक्ट पर दो लाख रुपए तक की वित्तीय मदद करेगा। कोरोना कर्फ्यू से काफी गतिविधियां बंद हैं, जिसका फायदा प्रोफेसर अपना रिसर्च वर्क पूरा करने में उठा रहे हैं। - डॉ. हरिहर शरण त्रिपाठी, रजिस्ट्रार

दिसंबर में 25 फीसदी राशि देने के आदेश हुए थे जारी

शिक्षकों को तीसरी किस्त के भुगतान का इंतजार

भोपाल। राजधानी के ज्यादातर शिक्षकों को सातवें वेतन की तीसरी किस्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मप्र शिक्षक कांग्रेस ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिसंबर में तीसरी किस्त की 25 फीसदी राशि देने के आदेश जारी हुए थे। पिछले मार्च में 75 फीसदी राशि का भुगतान करने के आदेश हुए इसके बावजूद अभी तक शिक्षकों को तीसरी किस्त नहीं मिल सकी। फंदा ब्लॉक के प्रत्येक शिक्षक को लगभग 70 से 80 हजार रुपए का भुगतान किया जाना था, जो अब तक नहीं किया गया। डीईओ नितिन सक्सेना का कहना है कि कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हैं, जो दफ्तर नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर शिक्षकों को भुगतान किया जा चुका है बाकी के बिल बन चुके हैं।

आदेश जारी होने के बाद भी दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों को नहीं मिल रही अनुग्रह राशि

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 366 शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन दिवंगत के आश्रित परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके लिए संबंधित परिवार या संस्था प्रमुख की ओर से संकुल केंद्र में पदस्थ वेतन आहरण अधिकारी को सूचना भेजी जाती है। बावजूद अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कार्यालय बंद रहने के चलते दिवंगतों के आश्रितों को तात्कालिक सहायता के रूप में मिलने वाली 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि तक नसीब नहीं हो रही है। लोक शिक्षण संचालनालय विभाग ने मार्च में नौ मार्च को एक आदेश जारी कर यह दिशा-निर्देश जारी किए थे कि अनुग्रह राशि का भुगतान आश्रित परिजनों को उसी दिन तत्काल दी जाए, लेकिन इसके बाद भी भुगतान में देरी हो रही है। पूरे प्रदेश में 1809 शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं और 366 की मौत हो चुकी है।

संविदा कर्मचारियों को मिले इलाज के लिए ढाई लाख

भोपाल। सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि संविदा कर्मचारियों को भी कोविड-19 के इलाज के लिए ढाई लाख रुपए दिए जाएं। संघ के अध्यक्ष ने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में करीब ढाई लाख संविदा कर्मचारी हैं, जो नियमित कर्मचारियों के समान ही कार्य करते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ की मांग

बोकारो की 'प्राणवायु' से भोपाल, जबलपुर ग्वालियर, सागर को मिली 'सांसें'

प्रशासनिक संवाददाता ■ भोपाल

कोरोना की तेजी से हो रहे संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की किल्लत बड़ी समस्या बन गई है। ऐसी स्थिति में देश के कोने-कोने से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन बुलाई जा रही है। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन 6 टैंकर ऑक्सीजन लेकर चली थी, जो देर रात सागर के मकरोनिया स्टेशन पर पहुंची। यहां तीन टैंकर रोके गए थे। जिनमें से एक टैंकर सागर के लिए रखा गया है और दो टैंकर ग्वालियर के लिए रवाना किए गए हैं। बाकी तीन टैंकर जबलपुर और भोपाल भेजे जाएंगे।

कहां-कहां पहुंचाए जाएंगे ऑक्सीजन के टैंकर

झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन के जो 6 टैंकर ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन से मध्य प्रदेश के लिए भेजे गए हैं। इनमें से तीन टैंकर सागर के मकरोनिया स्टेशन पर उतारे गए। एक टैंकर सागर के लिए रखा गया है, बाकी दो टैंकर ग्वालियर के लिए रवाना किए गए हैं। बाकी बचे तीन ऑक्सीजन टैंकर में से दो भोपाल के मंडीदीप के लिए भेज दिए गए हैं और एक टैंकर जबलपुर के लिए रवाना हो गया है।

जिला पंचायत सीईओ की मौजूदगी में उतारे टैंकर

बोकारो से ऑक्सीजन टैंकरों को अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे जिला पंचायत सीईओ इच्छित गड़पाले मकरोनिया स्टेशन पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में तीन टैंकर उतारे गए हैं।

ओडिशा से चार ऑक्सीजन टैंकर मध्यप्रदेश के लिए रवाना

पशुपालन विभाग के चार ऑक्सीजन टैंकर ओडिशा के अंगुल स्थित रिफाइनरी से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। पहला टैंकर 7,000 लीटर ऑक्सीजन लेकर गुना पहुंच गया है, बाकी तीन टैंकर ओडिशा से छतरपुर, जबलपुर और सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। टैंकर में 13 हजार 728 लीटर ऑक्सीजन है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि टैंकर चालक कृष्ण 6721.47 लीटर ऑक्सीजन के साथ गुरुवार को जबलपुर, चालक दीपचंद 3241.56 लीटर ऑक्सीजन के साथ सुबह 11 बजे सागर और चालक गौरव सिंह 3765.93 लीटर ऑक्सीजन के साथ दोपहर 12 बजे छतरपुर पहुंचेगा। ओडिशा शासन ने टैंकरों की सुरक्षा के लिए पुलिस वाहन भी उपलब्ध कराए हैं। इससे कई मरीजों को बचाने में सहायता होगी।

ऑक्सीजन टैंक की तौल के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे तौल उपकरण

प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले ऑक्सीजन टैंकर को तौलने के लिए सभी जिलों के तौलने के उपकरण 24 घंटे खुले रहेंगे। जिससे कि ऑक्सीजन आपूर्ति बिना देरी के सप्लाई केंद्रों तक पहुंच सके। यह आदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश ने दिए गए हैं। वे-ब्रिज को 24 घंटे चालू रखने की दी जाए परमिशनप्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने 26 अप्रैल को प्रदेश के सभी कलेक्टर को यह आदेश दिए हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण दूसरे प्रदेश से ऑक्सीजन टैंकरों के जरिए बुलाई जा रही है। इन टैंकर्स का तौल कांटा वे-ब्रिज पर किया जाता है। अगर हर जिले में लॉकडाउन की स्थिति है, तो ट्रक तौल कांटा वे-ब्रिज को आवश्यकता अनुसार 24 घंटे चालू रखने की परमिशन दी जाए, ताकि बाहर से आने वाले ऑक्सीजन के टैंकर का तौल कार्य करने में ज्यादा देर न हो और तौल कार्य तत्काल किया जा सके।

नगर निगम के ऑक्सीजन सेफ्टी ऑडिट में कई अस्पताल फेल!

भोपाल। महाराष्ट्र के एक अस्पताल में कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन प्लांट पर हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। इस घटना के मद्देनजर अब मध्य प्रदेश की राजधानी में भी अस्पतालों की ऑक्सीजन सेफ्टी ऑडिट की जा रही है। भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही यहां ऑक्सीजन की काफी किल्लत देखने को मिली है। राजधानी में ऑक्सीजन टैंक सुरक्षित रहे और समय पर लोगों को ऑक्सीजन मिल सके इसके लिए प्रशासन यह काम कर रहा है।

कई अस्पतालों में मिली खामियां

राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन सेफ्टी ऑडिट के लिए नगर निगम भोपाल के अपर आयुक्त सीपी गोहल की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। जो भोपाल के सरकारी और निजी अस्पतालों की जांच कर रहे हैं। टीम के सदस्य अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता और संसाधनों की जांच में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम भोपाल प्रभारी सहायक यंत्री पवन मेहरा ने अपनी टीम के साथ गांधी मेडिकल कॉलेज, जवाहर लाल नेहरू कैंसर अस्पताल, एलबीएस अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल लालपाटी में निरीक्षण किया। इस दौरान सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सेफ्टी में कई खामियां सामने आई हैं। अधिकारियों ने मौके पर ही लिखित रूप में प्रबंधन को पत्र लिखकर अस्पतालों में ऑक्सीजन सुरक्षा की स्थिति को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए हैं।

ऑपरेटर भी नहीं

राजधानी के अस्पतालों में नगर निगम की टीम को जो खामियां मिली है, उनमें ऑक्सीजन का बल्क स्टोरेज और, अग्निशमन यंत्रों का शामिल है। खास बात यह है कि ऑक्सीजन प्लांट के ऑपरेटर भी टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि अस्पताल प्रबंधन ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर गंभीर नहीं है और जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

कोविड वार्ड से परिजनों को वीडियो कॉल, ताकि बढ़े मरीज का आत्मविश्वास

भोपाल। हमीदिया अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिवार की चिंता कम करने और मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से अस्पताल में एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से कोविड वार्ड में भर्ती मरीज और उसके परिजनों के बीच वीडियो कॉल पर बात करवाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ानाऔर परिजनों की चिंता को कम करना है।

वीडियो कॉल से करवाई जाती है बात

हेल्पलाइन शुरू करने वाले वॉलिंटियर्स का कहना है कि कोविड वार्ड में भर्ती मरीज कई-कई दिन तक अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। इस दौरान उनके परिजनों को भी मरीज की चिंता होती है कि आखिर उनका हाल कैसा होगा. ऐसे में कुछ वॉलिंटियर्स ने इस सेवा की शुरुआत की है। ये सेवा हमीदिया अस्पताल के डी ब्लॉक में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए है। मरीजों के परिजन इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने अस्पताल में भर्ती अपने परिवार के सदस्य से वीडियो कॉल पर बात कर सकते है।

सिर्फ डी ब्लॉक में भर्ती मरीजों के लिए

हेल्पलाइन में काम कर रही कोरोना वालेंटियर रचना डोंगरा ने बताया कि हेल्पलाइन का नंबर 9329111487 है। ये हेल्पलाइन सिर्फ डी ब्लॉक में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए है। इस हेल्पलाइन पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक कॉल करके मरीज के परिजन अपने परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं। इस नंबर पर काल करके मरीज की जानकारी देने पर तुरंत ही उनके परिजनों से बात कराई जाती है। इस हेल्पलाइन के जरिए कोशिश की जाती है कि हर मरीज की कम से कम एक बार उनके परिजनों से वीडियो काल पर बात कराई जा सके।

बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विवि से पीएचडी की विदेशों में बढ़ी डिमांड

सांची विवि में प्रवेश परीक्षा के लिए आए 80 आवेदन, 12 फीसदी विदेशी विद्यार्थी

विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम तारीख में हुई बढ़ोतरी इससे विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए अब विदेशी विद्यार्थी भी खूब रुचि दिखा हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक विवि में करीब 80 आवेदन आए हैं, जिसमें से 12 फीसदी आवेदन दूसरे देशों के विद्यार्थियों ने किए हैं। इन आवेदनों में पांच श्रीलंका, दो म्यानमार और एक स्वीडन, एक वियतनाम और न्यूजीलैंड से जमा किए गए है। वहीं दूसरी ओर विवि पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा के फार्म जमा करने की अंतिम तारीख में भी एक फिर बढ़ोतरी की है, जिससे विदेशी विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। कुलपति नीरजा ए गुप्ता ने बताया कि रेगुलर के साथ पार्ट टाइम पीएचडी की व्यवस्था की गई है। इससे काफी शोधार्थियों को राहत मिलेगी। विवि ने एससी-एसटी और दिव्यांग विद्यार्थियों की परीक्षा फीस 1200। उनके अलावा सभी वर्ग की 1500 फीस निर्धारित की है। विवि ने विदेशी विद्यार्थियों की फीस में 66 फीसदी इजाफा किया है। एनआरआई विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने 2250 फीस का भुगतान करना होगा।

◆ कुलपति नीरजा ए गुप्ता ने बताया कि रेगुलर के साथ पार्ट टाइम पीएचडी की भी है व्यवस्था

अब तीस अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

विवि ने प्रवेश परीक्षा के फार्म जमा करने की अंतिम तारीख में एक बार फिर बढ़ोतरी करते हुए तीस अप्रैल कर दिया है। यानि अब विद्यार्थी तीस अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। पूर्व में अंतिम तिथि 26 अप्रैल तय की गई थी और 28 अप्रैल को योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी होनी थी। हालांकि तारीख बढ़ने बाद अब विवि तीन मई को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी।

चीनी भाषा में पीएचडी करने की चार सीटें

जानकारी के मुताबिक विवि बौद्ध अध्ययन, वैदिक अध्ययन, भारतीय शिक्षा एवं समग्र विकासए योग, भारतीय चित्रकला, हिन्दी, अंग्रेजी और चीनी भाषा में पीएचडी करा रहा है। ये विषय देश-विदेश के चुनिंदा विवि में संचालित हो रहे है। यहां तक उनके पास पीएचडी कराने की व्यवस्था नहीं हैं। लगातार विद्यार्थियों के डिमांड को देखते हुए कुलपति ने आवेदन करने की स्वीकृति दे दी है। विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। चीनी भाषा में पीएचडी करने चार सीटें रखी गई हैं।

नए शैक्षिणक सत्र से होगा लागू फैसला

सीबीएसई ने कक्षा 9,10,11 व 12वीं में परीक्षा का पैटर्न बदला

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं चारों कक्षाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया है। सीबीएसई का नया एग्जाम पैटर्न शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा। क एकेडेमिक सेशन 2021-22 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने नया असेसमेंट और ईवैल्यूएशन पैटर्न तैयार किया है। बोर्ड के ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट विभाग के निदेशक ▶▶ शेष पेज 6 पर

कक्षा 9-10 के लिए ऐसा पैटर्न

कक्षा 9वींऔर 10वीं की परीक्षा में कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 कर दिये गये हैं। इसमें मल्टीपल च्वाइस, केस आधारित और कोर्स आधारित इंटीग्रेडेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं, प्रश्नपत्र के 20% सवाल ▶▶ शेष पेज 6 पर

कक्षा 11-12 के लिए ये बदलाव

क्लास 11वीं और 12वीं की बात करें, तो पिछली बार की तरह कंपीटेंसी बेस्ड सवाल 20% होंगे। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों की संख्या 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। वहीं, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप सवाल 70% से घटाकर 60% कर दिए गए हैं।

कृषि उपज मंडियों की ई-अनुज्ञाओं में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई

भास्कर ब्यूरो, भोपाल| प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में ई-अनुज्ञाओं में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट अभी तक भोपाल स्थित मंडी बोर्ड मुख्यालय में नहीं आ पाई हैं जबकि मुख्यालय दो बार इस संबंध में मंडी बोर्ड के सात आंचलिक कार्यालयों यथा रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर एवं भोपाल को निर्देश दे चुका है। मंडी बोर्ड मुख्यालय ने 300 क्विंटल से अधिक मात्रा की ई-अनुज्ञाओं के सत्यापन के निर्देश दिये थे। पहले यह निर्देश जनवरी में जारी हुये और फिर मार्च माह में। लेकिन वर्तमान कोरोना महामारी के समय यह सत्यापन कार्य ठण्डे बस्ते में पड़ा हुआ है। दरअसल मंडी समितियों द्वारा 16 अगस्त 2019 से ई-मंडी अनुज्ञायें जारी करने का कार्य प्रारंभ किया था जिसमें 23 लाख 28 हजार 421 ई-अनुज्ञायें जारी की गईं और 1 करोड़ 67 लाख 38 हजार 382 भुगतान पत्रक जारी किये गये। ई-अनुज्ञा में कुछ ऐसी अनुज्ञायें भी जारी की गईं हैं जिनमें 300 क्विंटल से अधिक मात्रा की सिंगल अनुज्ञायें हैं। 300 क्विंटल से अधिक मात्रा की ई-अनुज्ञाओं में से 1 लाख 21 हजार 934, 400 क्विंटल से अधिक मात्रा की ई-अनुज्ञाओं में से 9 हजार 428 तथा 500 क्विंटल से अधिक मात्रा की ई-अनुज्ञाओं में से 2 हजार 964 अनुज्ञाओं का सत्यापन नहीं किया जा सका है तथा इन सभी 1 लाख 34 हजार 328 अनुज्ञाओं का सत्यापन करने के निर्देश आंचालिक कार्यालयों को दिये गये थे।

ई-अनुज्ञाओं के सत्यापन के निर्देश दिये गये थे। इनके जांच प्रतिवेदन फाईलों से ही देखकर बताये जा सकेंगे। अभी कोरोना महामारी के कारण दस प्रतिशत कर्मियों की ही उपस्थिति है, इसलिये इनके बारे में सही स्थिति नहीं ज्ञात नहीं हो सकती है। सभी जांच प्रतिवेदन आने के बाद ही इन्हें उच्च स्तर पर निर्णय के लिये पुटअप किया जायेगा।

- आरपी चक्रवर्ती, संयुक्त संचालक, एमपी मंडी बोर्ड, भोपाल

रेलवे ने अपने कर्मचारियों को दिया ई-ऑफिस का ऑनलाइन प्रशिक्षण

भोपाल। रेलवे क्षेत्र के बाहर रह रहे रेल कर्मियों को भोपाल मंडल ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई है। मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवणकर के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा वीपीएन के उपयोग की ट्रेनिंग भी दी गई। इससे वर्क फ्रॉम होम करते हुए फाइलों का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। रेलवे में ई-ऑफिस को मात्र रेलनेट पर ही प्रयोग किया जा सकता था। अभी तक यह सुविधा रेलवे क्षेत्र के बाहर उपलब्ध नहीं थी।

ट्रेनिंग

18 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों का एक मई से होगा टीकाकरण

भोपाल(आरएनएन)। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले के सभी नागरिकों से अपील की हैं कि कोरोना से बचाव की गाइड लाइन का पालन करें कोविड-19 संक्रमण को खत्म करने के लिये 01 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग भी वैक्सीन लगवायें। इसके लिए cowin.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करायें और वैक्सीनेशन सेंटर पर नंबर आने पर वैक्सीन लगवायें।

कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार को रोकने और संक्रमण खत्म करने के लिये वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवायें। इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करायें और वैक्सीनेशन सेंटर पर नंबर आने पर वैक्सीन लगवायें। कलेक्टर ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति स्वयं भी वैक्सिंग लगवाए और परिवार को भी वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाएं ताकि कोरोना को हराया जा सके। कलेक्टर श्री लवानिया ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के वाक्य का अनुसरण करें। उसके साथ ही दवाई भी और कड़ाई भी को भी आत्म सात करे, यह कोरोना संक्रमण से बचाव के कुछ बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय हैं। लोगों को यह सुनिश्चित करना है, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक चीजों को ना छूएं, भीड़-भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और लोगों से दो गज की दूरी बनाकर रहें। उन्होंने कहा कि उम्मीद है यदि हम सब इन नियमों का पालन करेंगे तो परिवार और अन्य लोगों को संक्रमण से बचा सकेंगे और कोरोना संक्रमण की गति को भी रोक पाएंगे।

उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या में बढ़ौत्तरी हो रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये जरूरी है कि घर से बाहर ना निकलें यदि घर से बाहर निकलना अति आवश्यक हो तो मास्क लगाकर ही निकलें, सार्वजनिक, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, चेहरे से मास्क नहीं हटाये। विशेषकर बात करते समय मास्क लगाये रखें, सार्वजनिक जगहों पर दो गज की दूरी बनाकर रखें, सर्दी, खांसी, बुखार आने पर कोरोना की जाँच तुरंत करायें एवं अन्य लोगों से दूरी बनाकर रखें।

बिजली कार्मिक टीकाकरण हेतु कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

भोपाल। राज्य शासन के निर्णयानुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी कार्मिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जायेगा। वैक्सीनेशन कार्यक्रम एक मई, 2021 से प्रारंभ किया जायेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि कंपनी के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी कार्मिकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस संबंध में क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधकों एवं महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि वृत्त एवं संभागीय स्तर पर कार्मिकों के टीकाकरण के लिये शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही महाप्रबंधक वृत्त कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं जिला कलेक्टर से संपर्क कर जिला स्तर पर शिविर लगाकर बिजली कार्मिकों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक कार्मिक के टीकाकरण के प्रमाण-पत्र का रिकार्ड पद-स्थापना स्थान कार्यालय में रखना सुनिश्चित करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बिजली कार्मिक राज्य शासन के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अनिवार्य रूप से टीकाकरण करायें।

कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों की अध्यापन गुणवत्ता पर रहेगा शिक्षक संघ का फोकस

वर्ष भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में निर्णय अक्टूबर में स्मारिका का विमोचन

भोपाल ■ राज्य न्यूज नेटवर्क

अपनी स्थापना के 50 साल पूरे करने पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। संगठन का दावा है कि मौजूदा वर्ष में लगातार शिक्षा के गुणात्मक विकास की दिशा में सफल कार्यक्रम आयोजित होंगे। विद्यालयों की दिशा और दशा बदलने के लिए संगठन विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से शासन तक सुझाव भेजेगा और उन पर अमल करवाने की कोशिश करेगा।

महामारी संक्रमण की दूसरी लहर में स्कूली बच्चों का गुणात्मक विकास करने के लिए संगठन द्वारा शीघ्र ही पूरे राज्य में यह कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू किये जा रहे है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

संघ पदाधिकारियों द्वारा कहा गया है कि ईर्ष्या द्वेष से परे सामूहिकता की भावना को लेकर, व्यक्तिगत हितों को दरकिनार कर कार्य करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं का यह संगठन है। अपने अधिकारों की रक्षा के साथ कर्तव्यबोध की भावना से संगठन को चलाना, प्रसन्न भाव से बच्चों के कल्याण के बारे में विचार करना यही शिक्षक संघ का कार्य होता है। जिसे शिक्षक संघ ने पूरा करने का सतत प्रयास किया है।

प्रत्येक शिक्षक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के बोध को ध्यान में रखकर वह अध्यापन कार्य करें, उसे विचार करना चाहिए कि मैंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर अपना आज का शिक्षण कार्य किया क्या क्योंकि प्रत्येक बात का रास्ता शिक्षा से होकर ही निकलता है। शिक्षा से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक संघ अपना लगे ऐसा प्रयास होना चाहिए।

पदाधिकारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने पिछले पचास वर्षों में अनेकों महत्वपूर्ण सोपान तय किए हैं और आज देश के एक शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित है। उन्होंने संघ की स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्षों की उपलब्धियों और रीतिनीति का ब्यौरा देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रत्यक्ष एकत्रीकरण संभव नहीं हो पाने के कारण आभासी पटल पर कार्यक्रमों का आयोजन बेहतर प्रयास है।

लगातार बढ़ाएंगे शिक्षा की गुणवत्ता

संगठन के प्रदेश महामंत्री क्षत्रवीर सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत पूरे वर्ष राज्य में शिक्षा के गुणात्मक विकास पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि संगठन से जुड़ा प्रत्येक पदाधिकारी विद्यालय में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति बढ़ाने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का कहर कम होने के बाद स्थिति सामान्य होते ही व्यापक स्तर पर प्रत्यक्ष बड़े कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाएगा एवं शिक्षा ज्ञान ज्योति यात्रा भी निकाली जाएगी। अक्टूबर 2021 में प्रदेश स्तरीय भव्य समारोह का आयोजन एवं स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा।

वर्चुअल बैठकर कर्मचारी संघ बढ़ा रहा लोक सेवकों का मनोबल

भोपाल। कोरोना संक्रमण से ध्यान रहे सरकारी लोक सेवकों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य कर्मचारी संघ द्वारा अभिनव पहल की गई है। इस संगठन द्वारा प्रदेश भर में वर्चुअल बैठकों का आयोजन कर कर्मचारियों के धैर्य और साहस में वृद्धि करने की तकनीक बताई जा रही है। संगठन का कहना है कि वर्चुअल बैठक एवं मोबाइल से संपर्क कर कोरोना पीड़ित परिवारों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही कोरोना टीका और उसकी गाइडलाइन की पालन करने का जन जागरण कर रहे हैं। अनेक पदाधिकारियों एवं परिवारों की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर शोक संवेदना भी वर्चुअल बैठक के दौरान शांति प्रार्थना कर रहे हैं। संगठन के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों की सूची जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे समय में यह सूची जमा करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस कारण सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखकर मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों की सूची जमा करने की समयावधि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। इसमें यह मांग भी की गई है कि प्रदेश में शासकीय सेवकों के स्थानांतरण को अभी न किए जाए। वर्चुअल व्यवस्था के अंतर्गत संभाग की बैठक आयोजित हुई। जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष बादाम सिंह यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल एडविन, संगठन मंत्री अनित भार्गव, कार्यालय मंत्री सुरेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश मंत्री अशोक शर्मा सहित शिवपुर मुरैना भिंड जिले के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उपस्थित रहे।

मंत्री को पत्र लिखकर मान्यता प्राप्त संघों की सूची जमा करने की अवधि बढ़ाने की मांग

योजना | कोरोना से निपटने के लिए शिवराज का मास्टर प्लान

ए ग्रुप में 18, बी ग्रुप में 16 और सी ग्रुप में 18 जिलों को किया शामिल

कोरोना आपदा की समीक्षा के लिए सरकार ने निकाला नया फॉर्मूला, ए, बी, सी ग्रुप में बांटे जिले

स्टार समाचार | भोपाल

कोरोना आपदा की समीक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब एक नया फॉर्मूला बनाया है। अब सभी जिलों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक साथ नहीं करेंगे। समीक्षा के लिए प्रदेश के सभी 52 जिलों को तीन अलग-अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। यह तीन ग्रुप ए बी और सी कैटेगरी में बनाए गए हैं।

ए ग्रुप में 18 जिले जबकि बी ग्रुप में 16 जिले और सी ग्रुप में 18 जिलों को शामिल किया गया है। इस कवायद के पीछे सरकार की कोशिश प्रदेश में कोरोना की स्थिति की बेहतर और सटीक समीक्षा करना है। अभी एक साथ सभी 52 जिलों की समीक्षा में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थीं। इसी को देखते हुए सरकार ने अब यह तय किया है कि जिले ग्रुप में बांटकर उनकी समीक्षा की जाएगी। ग्रुप ए के 18 जिलों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार शाम 4 बजे करेंगे। ज्ञात हो कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे है। इसी संक्रमण को कम करने के लिए सरकार ने अब नया प्लान बनाया है।

शिवराज की केंद्र से अपील

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से से अपील की है कि केंद्र से मुफ्त मिलने वाली वैक्सीन का उपयोग भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में करने की अनुमति मिले। बता दें कि 45 साल से ज्यादा उम्र के 1.29 करोड़ लोगों को जोड़ लिया जाए, तो अब 4 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है। इसके लिए 9 करोड़ 40 लाख डोज की जरूरत है। अब तक 45 से ज्यादा उम्र की 32% आबादी को ही वैक्सीन की पहली डोज ही लग पाई है।

नगरों में जल्द स्थापित करें विद्युत शवदाह गृह : मंत्री भूपेन्द्र सिंह

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगर की जनसंख्या के अनुरूप नगर में विद्युत/गैस शवदाह गृह बनाने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें। पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या के शहरों में आवश्यकानुसार एक से अधिक शवदाह गृह बनाए जा सकते है। एक लाख से 5 लाख तक की आबादी के शहरों में कम से कम एक विद्युत/गैस शवदाह गृह बनाने का लक्ष्य रखा जाए। सिंह ने कहा है कि किसी नगर में स्थापित विद्युत/गैस आधारित शवदाह गृह कार्यशील नहीं है, तो अतिशीघ्र उसे क्रियाशील करवाएं। व्यास ने कहा है कि विद्युत/गैस शवदाह गृह पर्यावरण, स्वच्छता तथा वायु प्रदूषण कम करने की दृष्टि से उपयोगी कदम है। इन शवदाह गृहों को स्थापित करने के लिए निकाय स्वयं की निधि, 15वें वित्त आयोग की वायु प्रदूषण, स्वच्छता हेतु प्राक्धानित राशि और विधायक, सांसद निधि का उपयोग कर सकते है।

किल कोरोना 2-अभियान शुरू, नौ मई तक चलेगा

बुखार के लक्षण वाले मरीजों की हो रही स्क्रीनिंग

भोपाल। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बुधवार से किल कोरोना दो अभियान की शुरूआत की गई है। इसके लिए घर-घर जाकर बुखार के लक्षण वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सैंपल भी लिए जाएंगे। यह अभियान नौ मई तक चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता, एएनएम, एमपीडब्ल्यू द्वारा घर-घर जाकर बुखार के लक्षण वाले कोरोना के संभावित मरीजों की खोज करेगी। बुखार के साथ अन्य लक्षणों जैसे विगत 10 दिवसों के भीतर सर्दी, खांसी, इंफ्लुएंजा लाइक इलनेस, पॉजिटिव व्यक्ति से संपर्क, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई, बदन दर्द, सिर दर्द के लक्षण दिखने पर रोगी की जानकारी सार्थक एप में दर्ज की जाएगी। वहीं जरूरत पड़ने पर इन्हें कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा।

टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाला पोर्टल हुआ क्रैश

भोपाल। देश में 18 और इससे ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन एक मई से शुरू होना। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से यानि 28 अप्रैल शाम 4 बजे से शुरू होना था, लेकिन 4 बजते ही कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल, 18 से 44 साल के लोग बिना रजिस्ट्रेशन के टीका नहीं लगवा सकेंगे। ऐसे में पोर्टल क्रैश होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में भी रजिस्ट्रेशन कर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मोबाइल नंबर डालने के बाद कई का ओटीपी नहीं आया, तो कई को ट्राय अगेन का मैसेज आ गया। लोग बार-बार ट्राय करते रहे। बता दें कि इंदौर में करीब 15 लाख लोगों को इस वर्ग में वैक्सीन लगना है। इंदौर में इस आयु वर्ग के करीब 15 लाख लोग हैं।

ग्रुप ए में शामिल जिले

इंदौर, उज्जैन, रतलाम, टीकमगढ़, धार, अनूपपुर, झाबुआ नीमच, देवास, निवाड़ी, मंदसौर, खरगोन, शाजापुर, आगर मालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर।

ग्रुप बी में शामिल जिले

भोपाल, ग्वालियर, बैतूल, दतिया, विदिशा, सीहोर, मुरैना शिवपुरी, होशंगाबाद, अशोक नगर, रायसेन, राजगढ़, गुना हरदा, श्योपुर, भिंड को बी ग्रुप में शामिल किया गया है।

ग्रुप सी में शामिल जिले

जबलपुर, रीवा, नरसिंहपुर, सिंगरौली, सीधी, पन्ना, सतना सागर, शहडोल, कटनी, छतरपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और दमोह जिला शामिल।

बैरसिया में 324 और फंदा में 234 आशा कार्यकर्ता करेंगी स्क्रीनिंग

लक्षणों में वृद्धि होने पर कोविड केयर सेंटर में भर्ती व्यक्तियों का सैंपल लेकर आवश्यकतानुसार डीसीएचसी में रेफर किया जाएगा। फीवर स्क्रीनिंग के लिए सर्वे दल को पल्स ऑक्सीमीटर, नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, पैरासिटामोल उपलब्ध कराया गया है। बैरसिया विकासखंड में 324 एवं फंदा विकासखंड में 234 आशा कार्यकर्ता भ्रमण कर फीवर स्क्रिनिंग कार्य किया जा रहा है।

CMA: अब 20 मई तक जमा होंगे फॉर्म

भोपाल। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीएमए) ने जून में होने वाली अपनी फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी हैं। सीएमए ने जून में होने वाली अपनी फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। इसके साथ ही परीक्षा का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी 20 मई तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन। वहीं, आइसीएमएआइ ने फाउंडेशन कोर्स परीक्षा का टाइमटेबल जारी कर दिया है। परीक्षा 23 जुलाई को दो शिफ्ट में होगी।

आज का इतिहास

- 1236-दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश का निधन हुआ।
- 1639-दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई।
- 1848-सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म।
- 1903-कनाडा के उत्तर-पश्चिम प्रदेश में हुए भूस्खलन से 70 लोगों की मौत।
- 1939-नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया।
- 1965-पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग ने अपने सातवें रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया।
- 1991-बांगलादेश के चटगांव में आए एक चक्रवाती तूफान में एक लाख 38 हजार लोग मारे गए और दस लाख लोग बेघर हो गए।

आज का इतिहास

1906 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर - हिन्दी के जाने-माने निबंधकार का जन्म हुआ।

1987 चौधरी चरण सिंह - भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री, जो किसानों की आवाज बुलन्द करने वाले प्रखर नेता माने जाते थे का निधन हुआ।

1972 पृथ्वीराज कपूर - हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष, जिन्होंने मुम्बई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया का निधन हुआ।

1999 नाइजीरिया में नागरिक सत्ता की स्थापना।

2008 भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

2008 इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट माइस्पेस के साथ ई-मेल सम्बन्धी समझौता किया।